बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 226 ● नई दिल्ली ● वीरवार 25 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

सिंधिया की कांग्रेस में वापसी पर कांग्रेस के दिग्गज नेता का बड़ा बयान, सियासी हलचल तेज

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि सत्ता और संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का लाभ उठाने के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले युवा नेताओं की पार्टी में कभी वापसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पीटीआई-वीडियो को दिए साक्षात्कार में यह भी कहा कि यह उनकी निजी राय है। उनका कहना है कि इस तरह के नेताओं को कांग्रेस में फिर से शामिल करने के बारे में विचार करना भी शर्मनाक होगा। रमेश ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस में बने रहे लोग वैचारिक रूप से पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं और पार्टी को फिर से मजबूत देखना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ युवा नेताओं ने सत्ता और संगठन में लाभ उठाने के बाद कांग्रेस छोड़ दी तथा ऐसी पार्टी का रुख किया जिसकी विचारधारा कांग्रेस से बिल्कुल विपरीत है।

6000 करोड़ के नशीले पदार्थ नष्ट करने के लिए ऑनलाइन ड्रग्स डिस्पोजल फोर्टनाइट कैंपेन शुरू होगा

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री द्वारा 6000 करोड़ रुपये मूल्य के 2,09,500 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए ऑनलाइन ड्रग्स डिस्पोजल फोर्टनाइट कैंपेन की शुरुआत की जाएगी। इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण पर विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029) और एनसीबी वार्षिक रिपोर्ट -2025 भी जारी होगी।

इसके अलावा गृह मंत्री, जम्मू और गुवाहाटी में एनसीबी के जोनल कार्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित यह बैठक, प्रधानमंत्री मोदी के नशामुक्त भारत के विज़न को साकार करने के सरकार के प्रयासों को और मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। यह बैठक हाइब्रिड मोड में 44 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रमुख हितधारकों के साथ-साथ राय सरकारों और ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 108 प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगी। केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों, मादक पदार्थ प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया यह विजन डॉक्यूमेंट, ड्रग की समस्या से निपटने के लिए मांग कम करने, आपूर्ति कम करने और नुकसान कम करने के पहलुओं पर एक साझा रोडमैप प्रदान करेगा। इस रोडमैप में नेटवर्क-केंद्रित प्रवर्तन अप्रोच की परिकल्पना की गई है। साथ ही, इसमें अगले तीन वर्षों के दौरान सिंथेटिक ड्रग्स और डार्कनेट के ज़रिए होने वाली तस्करी की चुनौतियों से निपटने, युवाओं को ड्रग्स से दूर रखने, और ड्रग्स का इस्तेमाल करने वालों के लिए इलाज व पुनर्वास केंद्रों की पहुँच बढ़ाने जैसे उपाय भी शामिल हैं। इन्हें समन्वित और निरंतर तरीके से लागू किया जाएगा। यह दस्तावेज़ सभी हितधारकों की जिम्मेदारियों, समय-सीमाओं एवं लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए, प्रवर्तन, मांग में कमी, पुनर्वास, जन-जागरूकता, क्षमता निर्माण और अंतर-एजेंसी समन्वय को एकीकृत करता है। यह विजन डॉक्यूमेंट देश भर में ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए नीति बनाने, उसे लागू करने और संस्थागत मज़बूती लाने के काम में एक मार्गदर्शक रूपरेखा के तौर पर काम करेगा। ड्रग डिस्पोज़ल फोर्टनाइट कैंपेन, नशीले पदार्थों को नष्ट करने का एक विशेष अभियान है। इस पखवाड़े के दौरान, देशभर में अलग-अलग केन्द्रीय और राय कानून-प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के अनुसार लगभग 2,09,500 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट किए जाने की उम्मीद है, जिनकी कीमत ?6,000 करोड़ रुपये बताई गई है। यह बैठक देश में मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए सभी सम्बन्धित हितधारकों द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों की व्यापक समीक्षा एवं मूल्यांकन के लिए एक मंच प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से सहभागी राज्यों, विभागों एवं एजेंसियों को नशीले पदार्थों पर प्रभावी नियंत्रण का लक्ष्य हासिल करने के लिए नए उत्साह एवं प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। गृह मंत्री ने देश में मादक पदार्थों की समस्या से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए सरकार का समग्र दृष्टिकोण, इस तरह की अप्रोच की आवश्यकता पर बल दिया है। यह उच्च-स्तरीय बैठक आगामी तीन वर्षों में देशभर में मादक पदार्थ तस्करी एवं मादक पदार्थों के दुरुपयोग से प्रभावी ढंग से निपटने से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगी।

दिल्ली में बच्ची से रेप-हत्या, आरोपी को गोली मारी

पुलिस का दावा- भागने की कोशिश कर रहा था; अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली ।दिल्ली में 11 साल की बच्ची से रेप और उसकी हत्या का आरोपी मंगलवार रात पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया। पुलिस का दावा है कि उसे क्राइम सीन रीक्रिएट करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसने भागने की कोशिश की। रोकने के लिए उसे पैर में गोली मार दी गई। फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित बच्ची गुब्बारा बेचती थी। सोमवार सुबह फुटपाथ पर सो रही थी। आरोप है कि टैक्सी ड्राइवर बबलू ने उसे अगवा किया। उसका रेप किया और हत्या कर लाश महरौली के जंगल में फेंक दी। सोमवार सुबह करीब 6 बजे परिवार ने पीसीआर कॉल के जरिए महरौली थाने में बच्ची की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से चार घंटे में ही बबलू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद कर लिया। पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि सड़क से गुजरते समय उसने सीडीआर चौक के पास फुटपाथ पर बच्ची को सोते हुए देखा था। उसने नींद में ही बच्ची को उठाया और कार की पिछली सीट पर लिटाकर महरौली के जंगलों में ले गया, जहां उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित परिवार फुटपाथ पर ही सोता था। बच्ची गुब्बारे बेचती थी, जबकि माता-पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। परिवार में चार बच्चे हैं, जिसमें ये 11 साल की बच्ची भी शामिल थी। महरौली पुलिस थाने से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। परिवार पहले किराए पर रहता था। गरीबी के चलते किराया नहीं दे पाए तो घर खाली करना पड़ा। इसके बाद परिवार फुटपाथ पर ही रहने लगा था। वहीं, एप बेस्ड कैब चलाने वाला आरोपी ड्राइवर भी बिहार का ही रहने वाला है। उसके ऊपर पहले से भी मारपीट और नशे में टैक्सी चलाने के कुछ केस दर्ज हैं।

कांग्रेस छोड़ने वाले युवा नेताओं की पार्टी में वापसी शर्मनाक होगा- जयराम रमेश का बड़ा बयान

नई दिल्ली । कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि सत्ता और संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का लाभ उठाने के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले युवा नेताओं की पार्टी में कभी वापसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पीटीआई-वीडियो को दिए साक्षात्कार में यह भी कहा कि यह उनकी निजी राय है। उनका कहना है कि इस तरह के नेताओं को कांग्रेस में फिर से शामिल करने के बारे में विचार करना भी शर्मनाक होगा।

रमेश ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस में बने रहे लोग वैचारिक रूप से पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं और पार्टी को फिर से मजबूत देखना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ युवा नेताओं ने सत्ता और संगठन में लाभ उठाने के बाद कांग्रेस छोड़ दी तथा ऐसी पार्टी का रुख किया जिसकी विचारधारा कांग्रेस से बिल्कुल विपरीत है। यह पूछे जाने पर कि योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और मिलिंद देवड़ा सरीखे नेता भविष्य में कांग्रेस में वापसी की कोशिश करते हैं तो क्या उन्हें वापस लेना चाहिए, तो रमेश ने कहा, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग सत्ता और संगठन में विभिन्न पदों रहते हुए लाभ उठाने के बाद, पार्टी के सबसे बड़े लाभार्थी होने के बावजूद पार्टी छोड़कर चले गए, उनके लिए वापस आने पर विचार करना भी हमारे लिए शर्मनाक होगा। उनका कहना था, एक बात निश्चित है कि पिछले 12 वर्षों ने यह साबित कर दिया है कि कौन लोग वास्तव में दृढ़ संकल्प वाले और संघर्षशील हैं। आज कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं, वे वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हैं। वे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से गहराई से जुड़े हुए हैं। वे चाहते हैं कि पार्टी फिर से मजबूत हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विशेष रूप से वे युवा लोग, जिन्होंने सत्ता का आनंद लिया, पदों और विशेषाधिकारों का लाभ उठाया, पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं, उन्होंने पार्टी छोड़कर ऐसी पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया जिसकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। उनका कहना था, क्या उन्हें वापस लिया जाना चाहिए? मैं इस बारे में अंतिम निर्णय लेने वाला व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन उन्हें वापस नहीं लिया जाना चाहिए। यह मेरी निजी राय है। पिछले कुछ वर्षों में योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह जैसे कई ऐसे नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, जो कभी कांग्रेस में प्रमुख चेहरे और राहुल गांधी के करीबी के रूप में देखे जाते थे।

भ्रष्टाचार पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन, दवा खरीद में गड़बड़ी के आरोपों पर दिए जांच के आदेश

नई दिल्ली ।दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय खरीद एजेंसी के माध्यम से दवाओं, सर्जिकल सामान और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 के तहत कार्रवाई शुरू की है। प्राप्त शिकायतों के आधार पर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर स्वास्थ्य सेवाओं की तत्कालीन महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और लेखा उप-नियंत्रक नीरज चोपड़ा की भूमिकाओं की जांच की जा रही है। जारी बयान में कहा गया है कि अब तक इस मामले के संबंध में केंद्रीय खरीद एजेंसी के प्रभारी डॉ. विनोद कुमार रंगा और डॉ. वत्सला अग्रवाल को निलंबित कर दिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने डॉ. विनोद कुमार रंगा को गिरफ्तार भी किया है। खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और सरकारी खजाने को हुए वित्तीय नुकसान के आरोपों की जांच चल रही है। इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जाए और मामले की नियमित समीक्षा और निगरानी का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो-टॉलरेंस (शून्य-सहिष्णुता) की नीति पर काम करती है। जनता की मेहनत की कमाई के हर पैसे की सुरक्षा करना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है, और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस बीच, इस पर साझा की गई एक अलग जानकारी में, मुख्यमंत्री ने 2.70 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना को मंजूरी देने की घोषणा की। आज कैबिनेट की बैठक में हमने दिल्ली के 2.70 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और उनके परिवारों के लिए दिल्ली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम से लगभग 10 लाख लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी का फायदा मिलेगा। हर वर्कर को 2 लाख रुपये तक और एक परिवार को 10 लाख रुपये तक की कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसमें सालाना हेल्थ चेक-अप, मोबाइल मेडिकल यूनिट, 24×7 हेल्पलाइन और अच्छी हेल्थ सर्विस शामिल हैं। एक्स पर आगे कहा गया, दिल्ली को बनाने वाले वर्कर भाई-बहनों को अब बीमारी की चिंता में अपनी जिंदगी भर की कमाई खर्च नहीं करनी पड़ेगी। दिल्ली सरकार उनके परिवारों की सेहत की जिम्मेदारी उठाएगी। अपनी मेहनत से राजधानी के सपनों को साकार करने वाले मजदूरों की सुरक्षा, सम्मान और सेहत हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

दिल्ली में उधार लिए 150 रुपये न देने पर किशोर की चाकू मारकर हत्या, 3 नाबालिग दबोचे

नई दिल्ली। तीन नाबालिगों ने तिलक नगर इलाके में एक 19 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वजह यह थी कि युवक ने उनमें से एक से उधार लिए 150 रुपये लौटाने से इंकार कर दिया था। पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर आरोपितों को पकड़ लिया है। पीड़ित पारस को 21 जून की रात हमले में कई चाकू के घाव लगे थे। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार, नाबालिगों ने घटना वाली रात रुपये के विवाद को लेकर पारस को घेर लिया था। पुलिस ने बताया कि झड़प होने के बाद वह मौके से भाग गया लेकिन तीनों ने लगभग 12-15 बजे रात फिर से उसे ढूंढ निकाला और हमला कर दिया। हमले के दौरान एक नाबालिग ने बार-बार चाकू से पारस को गोदा। पुलिस को पीड़ित की बहन से पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें उसने बताया कि उसके भाई को चाकू मार दिया गया है और उसे दीप दयाल उपाध्याय अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल के पास खून के निशान पाए। पीड़ित की बहन ने पुलिस को बताया कि वह अपने भाई को घर के पास घायल और बेहोश हालत में पड़ी हुई पाई थी।

तमिलनाडु की 152 मेडिकल सीटों पर अदालत सख्त, राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली । तमिलनाडु में सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल की 152 खाली इन-सर्विस सीटों को ऑल इंडिया कोटे में सरेंडर किए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को इस मामले पर केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अगर सरकारी डॉक्टर उच्च चिकित्सा कौशल हासिल करते हैं तो वे निजी डॉक्टरों की तुलना में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर तरीके से मजबूत कर सकते हैं। इस मामले को जुलाई में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए राय की 152 खाली इन-सर्विस सुपर स्पेशियलिटी सीटों को ऑल इंडिया कोटे में स्थानांतरित न किया जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन सीटों को तीसरे दौर या मॉप-अप काउंसलिंग तक राय के इन-सर्विस डॉक्टरों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक सरकारी डॉक्टर इन सीटों का लाभ उठा सकें।

जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इन-सर्विस डॉक्टरों की श्रेणी अलग होती है, क्योंकि ये डॉक्टर एक साथ सेवा भी दे रहे होते हैं और पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि सरकारी डॉक्टर विशेषज्ञता हासिल करते हैं तो इसका सीधा लाभ सरकारी अस्पतालों और आम मरीजों को मिलेगा।

अदालत ने इसी आधार पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कुल 430 सुपर स्पेशियलिटी सीटें काउंसलिंग के लिए उपलब्ध थीं। इनमें से 215 सीटें सरकारी सेवा में कार्यरत डॉक्टरों के लिए आरक्षित थीं। हालांकि, काउंसलिंग के दूसरे दौर तक केवल 63 सीटों पर ही दाखिला हो सका, जबकि 152 सीटें खाली रह गईं। अब इन सीटों को ऑल इंडिया कोटे में भेजे जाने की आशंका है, जिसका विरोध किया जा रहा है। तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि दूसरे चरण की ऑल इंडिया काउंसलिंग पूरी होने तक इन सीटों को सरेंडर करने पर रोक लगाई जाए।

सम्पादकीय...

संकल्प जल संचय का

आधुनिक युग में पृथ्वी का पर्यावरण एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां प्रकृति के संकेत अत्यधिक मुखर हो रहे हैं और ऋतुओं का पारंपरिक चक्र पूरी तरह प्रभावित होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूरदर्शिता से मई माह के अंत में ही स्पष्ट संकेत दिए थे कि इस बार गर्मी बहुत अधिक पड़ने वाली है। उन्होंने संपूर्ण देशवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति सजग रहने की भावपूर्ण अपील की थी। प्रधानमंत्री का यह आह्वान आज के इस अभूतपूर्व पर्यावरणीय संकट में देश को एक सुरक्षित दिशा दिखाने वाला मार्गदर्शक सिद्ध हो रहा है। वर्तमान समय में पृथ्वी का निरंतर बढ़ता तापमान और ऋतु चक्र में आ रहे तीव्र उतार-चढ़ाव इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि जलवायु परिवर्तन अब कोई भविष्य की दूरस्थ आशंका मात्र रहने के बजाय हमारे आज की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सामाजिक चुनौती बन चुका है। असमय होने वाली भारी वृष्टि, लंबे समय तक खिंचने वाला सूखा और ग्रीष्मकाल का यह हठ स्वरूप आज संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए गहरी चिंता का विषय है। इस वैश्विक वायुमंडलीय उथल-पुथल के ठीक केंद्र में प्रशांत महासागर से उत्पन्न होने वाली एक अत्यंत जटिल जल-मौसम वैज्ञानिक परिघटना है, जिसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में 'अल नीनो' के नाम से जाना जाता है। भारत जैसे विशाल, सघन जनसंख्या वाले और मूलतः खेती पर निर्भर देश के लिए अल नीनो का यह चक्र केवल किसी प्रयोगशाला के शोध का विषय भर ही नहीं रह सकता। यह सीधे तौर पर देश के करोड़ों किसान परिवारों के जीवन, उनकी आजीविका, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ अत्यंत गंभीर और व्यावहारिक प्रश्न है। समुद्र विज्ञान के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, सामान्य परिस्थितियों में प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पूरब से पश्चिम की ओर चलने वाली तेज व्यापारिक पवनें गर्म सतही जल को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की दिशा में धकेलती हैं। इसके प्रभाव से दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के पास समुद्र की गहराइयों से पोषक तत्वों से युक्त ठंडा पानी ऊपर की ओर आता है जो वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को संतुलित रखने में सहायक सिद्ध होता है और हमारे भारतीय मॉनसून को एक सकारात्मक संबल प्रदान करता है। परंतु, अल नीनो के प्रभाव काल में ये व्यापारिक पवनें अचानक शिथिल पड़ जाती हैं और कभी-कभी इनकी दिशा भी पूरी तरह विपरीत हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप समुद्र का यह गर्म सतही जल पश्चिम की ओर बढ़ने के बजाय वापस दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्रों की ओर लौटने लगता है। समुद्र की सतह का यह असामान्य तापन संपूर्ण वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्रों को उलट-पुलट कर देता है जिससे वैश्विक स्तर पर बादलों के बनने और उनके बरसने का पूरा भूगोल ही बदल जाता है। जहां पेरू के क्षेत्रों में इसके कारण अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की स्थितियां निर्मित होती हैं, वहीं दूसरी ओर भारत और दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में हवा का दबाव बढ़ जाता है जो हमारे मॉनसून की मानसूनी हवाओं की गति को कमजोर कर देता है। भारत के धरातल पर इसका सीधा असर वर्षा की भारी कमी, खंडित मानसून और ग्रीष्मकाल में रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी के रूप में परिलक्षित होता है। यह एक ऐसी वैज्ञानिक विभीषिका है जो देश के संपूर्ण जल विज्ञान चक्र और वाटर सर्कुलेशन को असंतुलित करने की पूरी क्षमता रखती है। इसके साथ ही, भूगोलीय स्तर पर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बदले स्वरूप और अल नीनो के इस प्रभाव ने मिलकर देश के सम्मुख एक अत्यंत जल संकट और मौसमी विक्षोभ की स्थिति उत्पन्न कर दी है। प्रधानमंत्री ने जल सुरक्षा को हमेशा से राष्ट्र की संप्रभुता और रक्षा सुरक्षा के समान ही सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। उनका स्पष्ट मत रहा है कि जल संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के दैनिक जीवन का एक स्वाभाविक संस्कार और एक विराट जन आंदोलन बनना होगा। इसी सोच के आधार पर उन्होंने 'कैच द रेन' अभियानों की शुरुआत की थी, जिसका मूल मंत्र यही है कि आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके हमें वर्षा के जल की एक-एक बूंद को वहीं सहेजना होगा जहां वह धरती पर गिरती है। वर्तमान सरकार ने देश के इतिहास में पहली बार 'जल शक्ति मंत्रालय' के रूप में एक एकीकृत और शक्तिशाली प्रशासनिक ढांचे का सृजन किया, जो देश के जल नियोजन (वाटर प्लानिंग) को एक नई, वैज्ञानिक और सुसंगत दिशा देने का एक अत्यंत युगांतकारी प्रयास साबित हुआ है। वहीं दूसरी ओर, 'अटल भूजल योजना' के अंतर्गत अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर भूजल स्तर का वैज्ञानिक प्रबंधन और पुनर्भरण किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र की स्थिरता के लिए 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के तहत 'प्रति बूंद अधिक फसल' के सिद्धांत पर ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का देशव्यापी विस्तार किया जा रहा है ताकि पानी के एक-एक अंश का सर्वोत्तम उपयोग हो सके। इसके साथ ही, जल निकायों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया 'अमृत सरोवर मिशन' अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रहा है, जिसके तहत देश के प्रत्येक जिले में न्यूनतम 75 ऐतिहासिक और नए तालाबों का निर्माण व जीर्णोद्धार करके स्थानीय जल स्रोतों को एक नया जीवन प्रदान किया जा रहा है। इन तमाम राष्ट्रीय पहलों के साथ-साथ सरकार 'रिवर इंटरलिंकिंग' (नदियों को आपस में जोड़ने) के सामरिक प्रोजेक्ट्स और समुद्र के खारे पानी को शुद्ध करने की आधुनिक 'डीसेलिनेशन' तकनीकों पर भी पूरी गति से काम कर रही है ताकि देश का कोई भी हिस्सा जल संकट से प्रभावित न रहे। जलवायु परिवर्तन और जल संकट की यह विकराल मार केवल मानव समाज की सीमाओं तक ही सीमित रहने वाली है। विकसित भारत बनने की राह में जल सुरक्षा और जल स्रोतों का संरक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत पहल सिद्ध होगी। 'जल है तो कल है' का यह कालजयी उद्घोष मात्र एक साधारण नारा रहने के बजाय मानव सभ्यता के अस्तित्व का सबसे बड़ा और अटल सत्य है। आज समय का यही तकाजा है कि हम सब मिलकर यह अटूट संकल्प लें कि हम पानी की प्रत्येक बूंद का संपूर्ण आदर करेंगे, इसके अनावश्यक अपव्यय को पूरी तरह रोकेंगे और अपने आसपास के पारंपरिक जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखकर उन्हें पुनर्जीवित करेंगे। बेजुबान जीव-जंतुओं के प्रति अपनी करुणा को अपने व्यवहार में उतारते हुए प्रकृति के साथ एक संतुलित, मर्यादित और आत्मीय संबंध स्थापित करना आज के समय की सबसे बड़ी पुकार है।

वैश्विक कूटनीति में भारत की बढ़ती भूमिका

रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए चल रहे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बीच एक दिलचस्प खुलासा सामने आया है। एक नई पुस्तक के अनुसार, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वर्ष 2025 की शुरुआत में सुझाव दिया था कि यूक्रेन में संभावित युद्धविराम लागू कराने के लिए भारतीय सैनिकों को शांति सैनिकों के रूप में तैनात किया जा सकता है। हालांकि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस प्रस्ताव ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और भूमिका को रेखांकित किया है। यह जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार मैगी हैबरमैन और जोनाथन स्वान की पुस्तक रेजीम चेंज- इनसाइड द इम्पीरियल प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप में सामने आई है। पुस्तक के अनुसार, 30 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस और रूस-यूक्रेन मामलों के विशेष दूत कीथ केलॉग सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। यह बैठक ऐसे समय हुई थी जब ट्रंप अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की रणनीति पर विचार कर रहे थे। चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने कई बार दावा किया था कि यदि वे सत्ता में आए तो इस युद्ध को 24 घंटे के भीतर समाप्त कर देंगे। हालांकि वास्तविकता कहीं अधिक जटिल साबित हुई। बैठक में कीथ केलॉग ने एक शांति योजना प्रस्तुत की, जिसे ट्रंप का ऐतिहासिक शांति समझौता कहा गया। इस योजना के तहत युद्धविराम की निगरानी के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड के सैनिकों को शांति सेना के रूप में तैनात करने का प्रस्ताव था। लेकिन जेडी वेंस ने इस विचार पर आपत्ति जताई। उनका तर्क था कि नाटो सदस्य देशों के सैनिकों की तैनाती रूस को उकसा सकती है। रूस लंबे समय से नाटो के विस्तार और उसकी सैन्य उपस्थिति को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता रहा है। उस समय रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी स्पष्ट कर चुके थे कि यूक्रेन में नाटो सैनिकों की तैनाती रूस के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य होगी। इसी संदर्भ में वेंस ने एक वैकल्पिक सुझाव दिया। उन्होंने पूछा कि क्या यूरोप के बाहर किसी अन्य देश के सैनिक इस भूमिका को निभा सकते हैं।

इसी दौरान उन्होंने भारत का नाम प्रस्तावित किया। पुस्तक के अनुसार, ट्रंप इस सुझाव पर मुस्कुराए और कहा कि भारतीय ऐसा नहीं करेंगे और न ही वे इस प्रकार के अभियान पर पैसा खर्च करना चाहेंगे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मित्रता का भी उल्लेख किया। यद्यपि यह प्रस्ताव कभी आधिकारिक स्तर पर भारत के समक्ष नहीं रखा गया, लेकिन यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक के नीति-निर्माता भारत को संभावित शांति रक्षक के रूप में देख रहे थे।

भारत की विदेश नीति लंबे समय से रणनीतिक संतुलन और संवाद पर आधारित रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन करने के बजाय शांति और बातचीत का रास्ता अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बातचीत की मेज पर निकाला जाना चाहिए। भारत की यही संतुलित नीति उसे इस संघर्ष में एक संभावित मध्यस्थ या विश्वसनीय शांति साझेदार के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत के रूस और पश्चिमी देशों दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। एक ओर रूस भारत का लंबे समय से रक्षा सहयोगी रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ भी भारत के रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। भारतीय सेना का संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अनुभवी शांति सैनिक योगदानकर्ताओं में से एक रहा है। भारतीय सैनिकों ने दक्षिण सूडान, लेबनान, सोमालिया, कांगो और कई अन्य संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र मिशनों के तहत सेवा दी है। इन अभियानों में भारतीय सैनिकों ने केवल युद्धविराम की निगरानी ही नहीं की, बल्कि मानवीय सहायता, नागरिकों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी अनुभव के कारण भारत को वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेदार और निष्पक्ष शांति साझेदार के रूप में देखा जाता है। हालांकि यूक्रेन का मामला अन्य शांति अभियानों से अलग है। यह केवल दो देशों के बीच युद्ध नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन से जुड़ा संघर्ष है। रूस, अमेरिका, यूरोप और नाटो जैसे बड़े खिलाड़ी इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। ऐसे में किसी भी शांति सेना की तैनाती अत्यंत संवेदनशील विषय बन जाती है। भारत के लिए भी ऐसी किसी भूमिका को स्वीकार करना आसान नहीं होता। यदि भारतीय सैनिक यूक्रेन में तैनात किए जाते, तो भारत को अपनी तटस्थता बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ता। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होता कि उसकी उपस्थिति को किसी पक्ष विशेष के समर्थन के रूप में न देखा जाए। दिलचस्प बात यह है कि अप्रैल 2025 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस विषय पर विचार व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि यदि वास्तविक युद्धविराम लागू होता है, तो भारत सीमित संख्या में शांति सैनिक भेजने पर विचार कर सकता है। उनके अनुसार यूरोप के बाहर के देशों को भी वैश्विक शांति प्रयासों में भागीदारी करनी चाहिए और भारत इस भूमिका के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हो सकता है। हालांकि भारत सरकार ने कभी औपचारिक रूप से इस संभावना पर कोई टिप्पणी नहीं की। नई दिल्ली का ध्यान लगातार युद्धविराम, मानवीय सहायता और कूटनीतिक समाधान पर केंद्रित रहा है। यह पूरा घटनाक्रम भारत की बदलती वैश्विक स्थिति को दर्शाता है। कुछ दशक पहले तक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में भारत को मुख्य रूप से क्षेत्रीय शक्ति के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। विश्व राजनीति में भारत की आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक क्षमता लगातार बढ़ रही है।

यही कारण है कि वैश्विक संकटों के समाधान में भारत की संभावित भूमिका पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अंततः, यूक्रेन में भारतीय शांति सैनिकों की तैनाती का प्रस्ताव भले ही केवल एक विचार के रूप में सामने आया हो, लेकिन यह भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय साख का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि विश्व की प्रमुख शक्तियां भारत को केवल एक क्षेत्रीय खिलाड़ी नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान देने वाली शक्ति के रूप में देखने लगी हैं। आने वाले वर्षों में यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है।

ममता के अस्तित्व का संकट

विगत 4 मई को प. बंगाल में चुनाव हारने के बाद ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस जिस तरह तिनके-तिनके होकर बिखर रही है, उसके नये-नये आयाम खुलने का दौर समाप्त ही नहीं हो रहा है और ताजा घटनाक्रम में पार्टी के विद्रोही विधायकों के साथ ही नगर निकायों के चुने हुए पार्षदों ने पृथक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाकर ममता दी को ही पार्टी के अध्यक्ष या चेयरपर्सन पद से हटा दिया है और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। निश्चित रूप से बंगाल की राजनीति में यह ऐसा अभूतपूर्व दौर है जिसमें चुनावी हार से ही पार्टी का पूरा ढांचा चरमरा गया है। बेशक तृणमूल कांग्रेस को 1998 में कांग्रेस से अलग होकर ममता दी ने ही खड़ा किया था और राज्य में तत्कालीन सत्तारूढ़ वामपंथी दलों के विरुद्ध सड़कों पर उतर कर उनके शासन को चुनौती दी थी जिससे उनके साथ बंगाल की आम जनता जुड़ती चली गई थी जिसके परिणामस्वरूप 2011 में उन्होंने वामपंथी दलों को मात देते हुए सत्ता का सिंहासन पाया और लगातार तीन चुनावों में अपनी पार्टी को विजय दिलाई मगर 2020 के आते-आते उन्होंने अपनी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को किसी पारिवारिक दल में बदलना शुरू किया और धीरे-धीरे अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना डाला जिसके विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस के निष्ठावान नेताओं के बीच भीतर ही भीतर रोष पैदा होना शुरू हुआ जो 2026 में उनकी पार्टी की पराजय होते ही फूटकर बाहर आ गया और उनकी पार्टी से विधायकों व सांसदों का पलायन शुरू हो गया। इसकी ताजा परिणिती बीते कल यह हुई कि तृणमूल पार्टी के कुल चुने हुए 80 विधायकों में 60 को लेकर अलग हुए नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी विधायकों व विभिन्न शहरों के चुने हुए पार्षदों ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी का एक विशेष अधिवेशन बुलाया और उसमें खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताते हुए ममता बनर्जी को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा कर उनके स्थान पर श्री अरूप राय को इस पद पर बैठा दिया। इस अधिवेशन में पार्टी की 30 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति का भी गठन किया गया और चार उपाध्यक्ष व चार महासचिव भी नियुक्त किये गये। पार्टी के इस गुट के अनुसार ममता बनर्जी उनकी मुख्य सलाहकार बनी रह सकती हैं। जाहिर है कि अब तृणमूल कांग्रेस में असली पार्टी होने की लड़ाई छिड़ेगी और विवाद चुनाव आयोग व न्यायालय तक भी जायेगा। मगर इससे पूर्व पार्टी के कुल 28 लोकसभा सदस्यों में से जिन 20 सांसदों ने विद्रोह किया था उन्होंने अपने गुट का विलय एक क्षेत्रीय नेशनल सिटीजंस पार्टी में करने का ऐलान करते हुए लोकसभा अध्यक्ष से सदन में अपने बैठने की अलग व्यवस्था करने की मांग की थी। राज्य स्तर पर तृणमूल कांग्रेस संगठन दो समानान्तर गुटों में विभक्त हो चुका है और राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक गुट नेशनल सिटीजंस पार्टी में तब्दील हो चुका है। इसे देखते हुए ममता दी के लिए अपने राजनीतिक अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। मगर तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि उनसे टूट कर केन्द्रीय व राज्य स्तर पर जितने भी नेता अलग हुए हैं उनका कोई जनाधार नहीं है और वे सभी चुनावों में ममता दीदी की लोकप्रियता के आधार पर जीते थे। अतः राजनीति कभी-कभी खुद को दोहराती भी है क्योंकि 1969 में हमने देखा था कि किस तरह कांग्रेस पार्टी में पहली बार विभाजन हुआ था और श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमन्त्री रहने के बावजूद संगठन में अकेली रह गईं थीं और पार्टी के सभी बड़े नेता संगठन कांग्रेस या सिंडीकेट में चले गये थे।

हर राज्य में तोड़-फोड़ की बिसात बिछी

अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने से सबको उम्मीद है कि अब होर्मुज की खाड़ी खुल जाएगी और कच्चा तेल आसानी से आने लगेगा तो तेल की कीमतें कम होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि भारत सरकार, तेल कंपनियों और सरकार समर्थक मीडिया की ओर से यह बात स्थापित कर दी गई है कि युद्ध के दौरान तीन महीने में तेल कंपनियों को बहुत बड़ा घाटा हुआ है। सो, यह धारणा बनाई गई है कि कंपनियां अपने घाटे की भरपाई करेंगी, जिसमें बहुत समय लगेगा। दूसरा कारण यह है कि भारत के लोग अब बढ़ी हुई कीमत के अभ्यस्त हो गए हैं। इसलिए वे दाम कम नहीं किए जाने का विरोध नहीं करेंगे, बल्कि इस बात पर खुश होंगे कि अब और कीमत नहीं बढ़ेगी। बहरहाल, समस्या सिर्फ पेट्रोलियम कंपनियों के घाटे की भरपाई की नहीं है। सरकार ने भी ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पेट्रोल और डीजल पर आयात शुल्क में कटौती की थी, जिससे सरकारी खजाने को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। सो, जब होर्मुज की खाड़ी खुलेगी, तेल की कीमत कम होगी और तेल की आवाजाही सुचारू हो जाएगी तो सबसे पहले सरकार अपने खजाने को भरेगी। दरअसल मोदी सरकार के लिए हर आपदा अवसर की तरह रही है। कोरोना के समय इसी तरह उत्पाद शुल्क बढ़ा कर सरकार ने पैसे कमाए थे और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत कम होने का लाभ लोगों को नहीं दिया था।

केसीआर का दांव आजमाएंगे केजरीवाल!

संकेत है कि अरविंद केजरीवाल चौंकाने वाला फैसला करते हुए पंजाब में समय से पहले चुनाव करा सकते हैं। वैसे तो पंजाब में अगले साल मार्च में चुनाव होना है, लेकिन बताया जा रहा है कि केजरीवाल उससे पहले नवंबर में चुनाव कराना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अचानक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को अगले चुनाव के लिए भी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए यह चर्चा शुरू हुई कि अब विधानसभा भंग करने की सिफारिश भगवंत मान कर सकते हैं। अगर अभी विधानसभा भंग होती है तभी छह महीने के भीतर यानी नवंबर या दिसंबर तक चुनाव होगा। अगर इसमें देरी होगी तो फिर चुनाव आयोग अगले साल मार्च में होने वाले अन्य राज्यों के चुनाव के साथ ही चुनाव कराएगा। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव का दांव आजमाना चाहते हैं। चंद्रशेखर राव मई 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उनके राज्य में चुनाव लोकसभा के साथ मई 2019 में होना था लेकिन उन्होंने 2018 के मध्य में विधानसभा भंग करा कर अक्टूबर में चुनाव कराया था और जीत गए थे। उनका मानना था कि लोकसभा और कई राज्यों के चुनाव कराने पर उनके एजेंडे का असर भी चुनाव पर होता है। केजरीवाल को भी ऐसा लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ पंजाब का चुनाव होगा तो उन राज्यों का असर पंजाब पर भी हो सकता है। इसलिए वे इसी साल अलग और अकेले चुनाव कराने का दांव चल सकते हैं।

ओवैसी उत्तर प्रदेश में काम पर लग गए

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश में अपना काम शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई क्योंकि चुनाव से ऐन पहले हुमायूं कबीर का एक स्टिंग वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वे कह रहे थे कि भाजपा के साथ उनकी डील हो गई है और वे भाजपा के कहने पर वोट काट रहे हैं। उन्होंने कई सौ करोड़ रुपये की डील होने की बात कही थी। हालांकि इसके बावजूद ईडी ने उनकी जांच नहीं की। लेकिन उनके स्टिंग वीडियो के बाद ओवैसी ने उनसे तालमेल खत्म कर लिया। कुछ सीटों पर उनकी पार्टी लड़ी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी ने अपना अभियान शुरू किया है। इस बार बहराइच से अभियान शुरू हुआ है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को निशाना बनाया गया है। ओवैसी की रैली से पहले ही सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह का विवाद शुरू हो गया। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि सुहेलदेव कोई राजा नहीं थे, राजा होते तो बहराइच में कोई किला होता। उन्होंने यहां तक कहा कि सुहेलदेव की पूरी कहानी काल्पनिक है। दूसरी ओर अनिल राजभर का कहना है कि गाजी की दरगाह सूर्य कुंड है और इसलिए दरगाह को तोड़ देना चाहिए। शौकत अली और अनिल राजभर के विवाद से जो ध्रुवीकरण होगा, उससे भाजपा को फायदा होगा और अखिलेश यादव का पीडीए वाले खेल बिगड़ेगा।

सपा सांसदों को लेकर संशय बढ़ा

समाजवादी पार्टी के सांसदों को लेकर संशय बढ़ गया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओमप्रकाश राजभर ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में टूट हो सकती है। इस सिलसिले में उन्होंने रामगोपाल यादव के अमित शाह से मिलने का जिक्र किया है। हालांकि शिवपाल यादव ने कहा कि इन बातों में कोई दम नहीं है और सैफई परिवार एकजुट है। हो सकता है कि सैफई परिवार एकजुट हो लेकिन पूरी सपा तो सैफई परिवार नहीं है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता संशय में हैं। उन्हें लग रहा है कि भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण हुआ तो अगला चुनाव मुश्किल होगा। कई सपा सांसदों के बारे में खबर है कि वे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं या अपने परिवार में किसी को टिकट दिलाना चाहते हैं और मान रहे हैं कि भाजपा में जीतने के चांस ज्यादा है। हालांकि अखिलेश यादव ने भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति का माहौल बनाया है। वैसे अभी राममंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले से भाजपा बैकफुट पर आई है। फिर भी कहा जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी नहीं भी टूटती है तो भाजपा की योजना मानसून सत्र में परिसीमन बिल पर कुछ सांसदों को गैरहाजिर कराने की है। पिछली बार अलग अलग पार्टियों के एक दर्जन सांसद गैरहाजिर रहे थे। इस बार 20 सांसदों को गैरहाजिर कराने की योजना है, जिसमें इंडिया गठबंधन की तीन प्रादेशिक पार्टियों सपा, राजद और जेएमएम पर नजर है।

शरद पवार की पार्टी भी संकट में

आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिव सेना को तोड़ने के बाद भाजपा के निशाने पर अब शरद पवार की पार्टी है, जिसके चलते संसद के मानसून सत्र से पहले सबसे बड़े मराठा क्षत्रप शरद पवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उद्धव ठाकरे के नौ में से छह सांसद एकनाथ शिंदे की शिव सेना में जा रहे हैं। इस बीच शरद पवार की एनसीपी के आठ सांसदों में से पांच या छह के टूटने की चर्चा शुरू हो गई है। शरद पवार पर उनकी पार्टी के नेता दबाव डाल रहे हैं कि वे अपनी पार्टी का विलय सुनेत्रा पवार की एनसीपी के साथ कर दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो कई सांसद और विधायक पाला बदल सकते हैं। उनकी पार्टी के सांसद मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर विलय हो जाता है तो शरद पवार खेमे के भी कुछ लोगों को महाराष्ट्र सरकार में जगह मिल जाएगी और उनकी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बना दिया जाएगा। इस तरह परिवार के सभी सदस्यों की भूमिका स्पष्ट हो जाएगी। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र में तो सुप्रिया दिल्ली में राजनीति करेंगी। पता नहीं सुनेत्रा पवार इस व्यवस्था में कितनी महत्व होंगी। अपने बेटे पार्थ पवार को लेकर उनकी बड़ी योजना है और उनको यह भी लग रहा है कि उसके

जलवायु परिवर्तन की भयावह चेतावनी

जून 2026 में यूरोप एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में है। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन और बेल्जियम जैसे देशों में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। कई क्षेत्रों में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि कुछ स्थानों पर इससे भी अधिक गर्मी की आशंका जताई गई है। यह केवल एक मौसमी गर्मी नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों का स्पष्ट संकेत है। इस भीषण गर्मी ने न केवल जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर डाला है। फ्रांस इस संकट का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री ने बताया कि 18 जून के बाद से केवल कुछ दिनों में 40 लोगों की डूबने से मृत्यु हो चुकी है। अत्यधिक गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नदियों, झीलों और नहरों में तैरने के लिए उतर रहे हैं, जिनमें से कई स्थान सुरक्षित नहीं हैं। खेल मंत्री मरीना फेरारी ने लोगों को अनधिकृत क्षेत्रों में तैराकी न करने की चेतावनी दी है। लेकिन जब तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहे, तब लोगों के लिए राहत के साधन सीमित हो जाते हैं। इस गर्मी की सबसे दर्दनाक घटनाओं में फ्रांस के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में दो छोटे बच्चों की मौत भी शामिल है। दोनों बच्चे अपनी मां की कार में बेहोश पाए गए और चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। यह घटना दर्शाती है कि अत्यधिक तापमान केवल असुविधा का कारण नहीं बल्कि जानलेवा खतरा भी बन सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस गर्मी की वजह एक विशेष मौसमीय प्रणाली है जिसे ओमेगा ब्लॉक कहा जाता है। इसका नाम यूनानी अक्षर ओमेगा के आकार पर रखा गया है। इस व्यवस्था में गर्म हवा का एक विशाल गुंबद पश्चिमी और मध्य यूरोप के ऊपर स्थिर हो जाता है। इसे हीट डोम भी कहा जाता है। यह गर्म हवा को ऊपर उठने या बाहर निकलने नहीं देता, जिसके कारण तापमान लगातार बढ़ता रहता है। परिणामस्वरूप कई दिनों तक भीषण गर्मी बनी रहती है और रात में भी पर्याप्त राहत नहीं मिलती। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि ओमेगा ब्लॉक जैसी मौसमीय घटनाएं प्राकृतिक रूप से होती हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन उनके प्रभाव को और अधिक गंभीर बना रहा है। विश्व मौसम संगठन के अनुसार यूरोप वैश्विक औसत की तुलना में दो गुना तेजी से गर्म हो रहा है। पिछले चार दशकों में यूरोप का तापमान लगातार बढ़ा है और अब यह दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बन चुका है। ब्रिटेन में भी स्थिति चिंताजनक है।

मौसम विभाग ने दक्षिणी इंग्लैंड में 37 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने की संभावना जताई है, जो जून महीने के लिए नया रिकॉर्ड हो सकता है। कई स्कूलों ने समय से पहले छुट्टी करने का निर्णय लिया है क्योंकि पुराने भवनों में इतनी गर्मी में बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। कई कक्षाओं में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्पेन में हालात और भी गंभीर हैं। देश के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुछ क्षेत्रों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि अंदुजार क्षेत्र में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। रात के समय भी तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा रहा, जिससे लोगों को आराम और नींद दोनों में कठिनाई हो रही है।

इटली में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 शहरों के लिए उच्चतम स्तर की चेतावनी जारी की है। सरकार ने निर्माण और अन्य बाहरी कार्यों में काम के घंटे सीमित करने जैसे कदम उठाए हैं ताकि श्रमिकों को अत्यधिक गर्मी से बचाया जा सके। वहीं बेल्जियम में एक प्राथमिक विद्यालय को अपने अंतिम परीक्षा केंद्र को चर्च में स्थानांतरित करना पड़ा क्योंकि स्कूल की इमारत में पढ़ाई और परीक्षा आयोजित करना मुश्किल हो गया था। गर्मी का प्रभाव केवल लोगों के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। परिवहन नेटवर्क भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। फ्रांस में पेरिस और ब्रसेल्स के बीच कुछ रेल सेवाएं रद्द करनी पड़ीं। ब्रिटेन में रेलवे प्रबंधन ने यात्रियों से केवल आवश्यक यात्रा करने की अपील की है। अत्यधिक गर्मी के कारण रेल पटरियों और अन्य बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण ट्रेनों की गति कम करनी पड़ती है। आर्थिक गतिविधियों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। फ्रांस के उद्योग संगठनों ने स्वीकार किया है कि गर्मी के कारण कामकाज की गति धीमी पड़ गई है। कई व्यवसाय अपने कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए कार्य समय में बदलाव कर रहे हैं। पेरिस में बिजली से चलने वाले पंखों की मांग इतनी बढ़ गई कि कई दुकानों में उनका स्टॉक समाप्त हो गया। यह स्थिति दर्शाती है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं बल्कि आर्थिक चुनौती भी बन चुका है। इस संकट की तुलना अक्सर 2003 की ऐतिहासिक यूरोपीय हीटवेव से की जा रही है। उस समय फ्रांस में लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। अधिकांश मृतक बुजुर्ग थे जो बिना एयर कंडीशनिंग वाले घरों और वृद्धाश्रमों में रह रहे थे। उसी त्रासदी के बाद फ्रांस ने विशेष हीटवेव चेतावनी प्रणाली विकसित की थी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां यह संकेत देती हैं कि भविष्य में ऐसे संकट और अधिक बार सामने आ सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पिछले चार वर्षों में यूरोप में गर्मी से संबंधित कारणों से दो लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और इनमें से अधिकांश मौतें रोकी जा सकती थीं। गर्मी से शरीर में पानी की कमी, हीट एक्सॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो समय पर उपचार न मिलने पर जानलेवा साबित हो सकती हैं। कुल मिलाकर यूरोप की वर्तमान हीटवेव केवल एक मौसमीय घटना नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन की गंभीर चेतावनी है। बढ़ता तापमान, स्वास्थ्य संकट, आर्थिक नुकसान और बुनियादी ढांचे पर दबाव यह स्पष्ट करते हैं कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिक प्रभावी और त्वरित कदम उठाने होंगे। यदि वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस नीतियां नहीं अपनाई गईं, तो आने वाले वर्षों में ऐसी गर्मी और अधिक घातक तथा विनाशकारी रूप ले सकती है। यूरोप का वर्तमान संकट पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता बन चुका है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार घाती ने कन्दन ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार घाती, मो0 : 09582093548, समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2014/[illegible])

भाजपा नेता राधेश्याम शुक्ला जिला बदर, आधा दर्जन मुकदमों के इतिहास पर एडीएम कोर्ट का फैसला

देवरिया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) की कोर्ट से गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई

पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष व भाजपा नेता का रहा है लंबा आपराधिक इतिहास

जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने और आपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। कलेक्ट्रेट स्थित अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) की न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत शहर के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष और भाजपा नेता राधेश्याम शुक्ला को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है। पुलिस महकमे की रिपोर्ट और लंबे आपराधिक इतिहास के मूल्यांकन के बाद गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत यह सख्त प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इस आदेश के बाद से ही स्थानीय सियासत और आपराधिक तत्वों में हड़कंप का माहौल है। प्रशासनिक आदेश के मुताबिक, कोतवाली थाना क्षेत्र के मेहड़ा पुरवा निवासी राधेश्याम शुक्ला (पुत्र चंद्रमान शुक्ला) के खिलाफ पिछले डेढ़ दशक से अधिक समय से विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उनके खिलाफ वर्ष 2008 में गौरीबाजार थाने में अपहरण का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद वर्ष 2010, 2013 और 2018 में रंगदारी, मारपीट, घर में घुसकर तोड़फोड़ और धमकी देने के संगीन आरोप में कोतवाली में मुकदमे कायम हुए। इसके अलावा वर्ष 2021 में शस्त्र अधिनियम और हाल ही में वर्ष 2025 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार दी गई रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने पाया कि उनकी समाज में सक्रियता शांति व्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं है। जारी आदेश के तहत राधेश्याम शुक्ला को देवरिया जनपद की भौगोलिक सीमाओं से अगले छह महीने के लिए निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासन अवधि के दौरान उन पर प्रशासनिक निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही, आदेश में यह अनिवार्य शर्त लगाई गई है कि उन्हें प्रत्येक महीने की 3 और 27 तारीख को संबंधित कोतवाली थाने में उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि इस प्रतिबंधात्मक आदेश का किसी भी स्तर पर उल्लंघन किया गया या जनपद की सीमा में अनधिकृत प्रवेश पाया गया, तो उनके विरुद्ध तत्काल नई कठोर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।

महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर मेधावी छात्रों और छात्राओं को किया गया पुरस्कृत

गोरखपुर।

गोकुल अतिथि भवन गोरखपुर में आयोजित 24 जून को गोंडवाना कि गोंड विरांगना महारानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर मूलनिवासी आदिवासी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव शंकर गोंड जी ने गोंड,धुरिया समाज के तथा सामाजिक संस्था और शासन व प्रशासन के पदाधिकारियों को नियंत्रण पत्र दिया गया था और कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मेधावी छात्रों और छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। उक्त कार्यक्रम में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव शंकर गोंड जी ने मुख्य वक्ता के तौर पर कहा कि धुरिया गोंड अनुसूचित जनजाति वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के तमाम शासनादेश आदेश निर्देश तथा उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी जिला के शासन प्रशासन कि हिला हवाली को अब निर्णायक रूप दिया जाएगा जिसका सोपान है संगठित होना तथा अपने कागजात सबूत को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना तथा अपनी रुढ़ी परम्परा के प्रति जागरूकता अभियान जारी करना है। मंच का संचालन कर रहे शुभम गोंड जी ने कड़े शब्दों में कहा कि महारानी दुर्गावती जी के बलिदान से यह सिख मिलता है कि हमें अपने आन बान शान के अपने समाज के हित में यदि प्राण लेना हो या स्वयं आत्म बलिदान कि बात आये तो पीछे नहीं हटना चाहिए और समाज के उत्थान के लिए किसी के बहकावे में नहीं बल्कि अपने सगे संबंधियों के साथ संगठित होकर अनुसूचित जनजाति वर्ग कि जागरूकता में सहभागीता निभाएं और निरन्तर विकास कि ओर कार्य करते रहे।

संस्था के प्रदेश अध्यक्ष और विधि सलाहकार एडवोकेट दिनेश चन्द्र गोंड जी ने मंच का संचालन करते हुए कहा कि गोंडवाना कि गोंड वीरांगना महारानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस 24 जून को ही प्रदेश स्तर पर हर वर्ष मनाया जाएगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के गोंड समाज के उत्थान के लिए निवासरत समाज के प्रत्येक व्यक्ति कार्यक्रम में उपस्थित होकर सहभागिता करें और संस्था द्वारा जनगणना फार्म को भरें तथा जमा करें और समाज के लोगों को जोड़ने में उत्थान में देश के विकास में सहयोग करें और इस जन-जागरूकता में सहभागी बनें। मुख्य अतिथि राकेश गोंड जी ने कहा कि धुरिया गोंड सामाज कि जागरूकता के लिए रुढ़ी परम्परा के तहत आगामी सवनही पुजा और विश्व आदिवासी दिवस पर सभी लोगों को आने का संदेश दिया।शिवशंकर गोंड राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभम गोंड, दिनेश चन्द्र गोंड एडवोकेट राकेश जी, योगेश गोंड प्रधान जी,भोला गोंड शुभम गोंड मेहरा, मुन्ना गोंड पुर्व प्रधान प्रत्याशी, राजू गोंड,सुरज गोंड, दीपक गोंड,डिग्री प्रसाद गोंड , सुरेन्द्र प्रसाद, अश्विनी, दुर्गेश,सुरेश, प्रशान्त कुमार, धुरिया गोंड अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज के हजारों लोग उपस्थित रहे ।

मुख्य सेविकाओं की कार्यक्षमता जांचने को कलेक्ट्रेट में परीक्षा, डीएम ने खुद परखा ज्ञान

देवरिया।

बाल विकास एवं पुष्ठाहार विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ लागू करने के लिए जिला प्रशासन ने एक अनूठा प्रशासनिक प्रयोग किया है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देश पर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में तैनात सभी 71 मुख्य सेविकाओं की क्षमता संवर्धन हेतु एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा के माध्यम से मुख्य सेविकाओं को विभागीय योजनाओं, गतिविधियों और नियमों पर आधारित एक विशेष प्रश्नावली दी गई, जिसके आधार पर उनकी कार्यक्षमता और ज्ञान का धरातलीय मूल्यांकन किया गया। प्रशासनिक स्तर पर उठाए गए इस कदम का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के कार्यों की सटीक मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना है।

परीक्षा के नतीजों के आधार पर इन मुख्य सेविकाओं के लिए एक विशेष कैपेसिटी बिल्डिंग (क्षमता संवर्धन) प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके बाद इन्हें फील्ड में आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रभावी निरीक्षण, गृह भ्रमण के तौर-तरीकों, वीएचएसएनडी (ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण) सत्रों को सुदृढ़ करने तथा सहयोगी पर्यवेक्षण के लिए नए सिरे से प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि ग्रामीण अंचलों में मातृ-शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाई जा सके और कुपोषण के खिलाफ जंग को गति मिले। ?सभागार में मुख्य सेविकाओं को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कहा कि परीक्षा और प्रशिक्षण विभागीय कार्यप्रणाली को धार देने का एक सशक्त माध्यम है।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित अनियमितताओं की जांच की मांग, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

कुशीनगर।

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित चंदा एवं चढ़ावे की धनराशि में कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े समाचारों के सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। जिला कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष तारकेश्वर सिंह के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। जिला उपाध्यक्ष तारकेश्वर सिंह ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यदि चढ़ावे और चंदे की धनराशि के दुरुपयोग, गबन अथवा चोरी जैसी घटनाएं हुई हैं तो यह न केवल गंभीर आपराधिक मामला है, बल्कि करोड़ों रामभक्तों की भावनाओं के साथ भी अन्याय है। ऐसे मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि पूरे प्रकरण में तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही मंदिर में प्राप्त चंदा एवं चढ़ावे के लेखा-जोखा का स्वतंत्र ऑडिट भी कराया जाए।

ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पारदर्शी वित्तीय निगरानी व्यवस्था लागू की जाए, जिससे श्रद्धालुओं का विश्वास और आस्था अक्षुण्ण बनी रहे। इस अवसर पर मुहम्मद जहीरूद्दीन, संजय कुमार शाही, राज कपूर राय (एडवोकेट), धनंजय सिंह, सरोज कुमार गौतम, सुरेंद्र सिंह, गोरख यादव, पलटन यादव, अंगद चौहान, जे.एन. सिंह, स्वामीनाथ यादव, आर्यन, आफताब आलम, अब्दुल हामिद अंसारी, मुस्लिम अंसारी एवं राजू कुशवाहा सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सात दिन से लापता युवक का नर कंकाल मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

कुशीनगर। हाटा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गौदहा धनहा में सड़क किनारे सरपत (झंकार) में एक युवक का नर कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके की जांच कर हड्डी अवशेषों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार मंगलवार 24 जून को ग्रामवासियों ने सूचना दी कि साधु शाही भट्टे के सामने सड़क किनारे सरपत में एक शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो मृतक की पहचान योगेश कुमार पुत्र राम प्यारे निवासी गौदहा धनहा, थाना हाटा के रूप में हुई। शव पूरी तरह नर कंकाल की अवस्था में था। परिजनों ने मृतक की पहचान उसके चप्पल और गमछे के आधार पर की। पुलिस ने बताया कि मृतक के सभी हड्डी अवशेषों को पीएम किट में सुरक्षित रखकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की गई और पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी हाउस रविंद्र नगर भेज दिया गया है। बताया गया कि मृतक के पिता राम प्यारे ने 22 जून को हाटा थाने में लिखित तहरीर देकर बताया था कि उनका पुत्र योगेश कुमार 17 जून से घर से लापता है। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका था। इस सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। क्षेत्राधिकारी कसया कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण की हर पहलू से जांच कराई जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

डीजे पर डांस को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार, एक बाल अपचारी अभिरक्षा में

कुशीनगर। सेवरही थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने और डांस करने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार 22 जून 2026 की रात शादी समारोह में डीजे पर डांस करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर हुई मारपीट के दौरान सुजीत चौहान पुत्र अमन चौहान निवासी बसडीला पाण्डेय थाना तुर्कपट्टी को चाकू मार दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में थाना सेवरही पर मुकदमा संख्या 148/2026 धारा 191(2), 191(3), 103(1) एवं 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने राहुल गोड़ पुत्र शम्भू गोड़, गोलू रौनियार पुत्र मनोज रौनियार, ज्योति चौहान उर्फ अजीत चौहान पुत्र स्वर्गीय किशुन चौहान तथा दिनेश कुमार उर्फ धनंजय चौहान पुत्र दिलीप चौहान को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी थाना सेवरही क्षेत्र के निवासी हैं। इसके अलावा एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय भेजा जा रहा है, जबकि बाल अपचारी के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह, उपनिरीक्षक आकाश सिंह, उपनिरीक्षक अनिल शर्मा, हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह, कांस्टेबल धर्मेन्द्र यादव तथा कांस्टेबल अमित सिंह शामिल रहे।

सिवनी मालवा प्रकरण में 14 गौसेवकों को राहत देने की मांग

महराजगंज।

सिवनी मालवा प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा पाए 14 गौसेवकों को राहत दिलाने की मांग को लेकर बुधवार को राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मानवीय एवं संवैधानिक आधार पर मामले में पुनर्विचार करने और अनुच्छेद 161 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई का अनुरोध किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष विशाल पुष्कर ने कहा कि सिवनी मालवा प्रकरण में 14 गौसेवकों को आजीवन कारावास का दंड दिया जाना देशभर के गौभक्तों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के बीच गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौसेवा को सेवा, करुणा एवं लोककल्याण का प्रतीक माना गया है। इस प्रकरण में दोषसिद्ध व्यक्तियों के परिवारों पर सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ज्ञापन में कहा गया कि न्याय व्यवस्था के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए हमारा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकरण पर मानवीय एवं संवैधानिक दृष्टिकोण से पुनर्विचार किया जाए। भारतीय संविधान में दया, क्षमा, दंड-लघुकरण, दंड-परिवर्तन तथा समयपूर्व रिहाई जैसे विषयों के संबंध में विशेष प्रावधान हैं। संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर दोषसिद्ध व्यक्तियों को राहत देने की शक्ति देता है। समय-समय पर विभिन्न राज्यों में इस प्रावधान का उपयोग करते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया है।

राष्ट्रीय बजरंग दल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

विशाल पुष्कर ने मांग की कि सिवनी मालवा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों का निष्पक्ष, न्यायोचित एवं मानवीय आधार पर पुनः परीक्षण कराया जाए। दोषसिद्ध व्यक्तियों के आचरण, सामाजिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक परिस्थितियों और कारावास के दौरान उनके व्यवहार सहित सभी तथ्यों का मूल्यांकन किया जाए। यदि विधिसम्मत पाया जाए तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल के समक्ष आवश्यक अनुशंसा भेजी जाए।इस दौरान सोनू आचार्य, सचिन पाण्डेय, आदर्श सनातनी, सत्यदेव उर्फ सत्या, सूरज तिवारी, अविनाश प्रजापति, शुभम मिश्रा, कृष्णमोहन मलेशिया, विजय सैनी, अतुल मणि त्रिपाठी, सदर ब्लाक अध्यक्ष अरुण सनातनी, मिठौरा ब्लाक अध्यक्ष अंकुर चौधरी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

भरत भूषण तिवारी को नहीं मिला न्याय तो सीएम आवास का करेंगे घेराव, प्रशांत किशोर का बिहार सरकार को अल्टीमेट

नेशनल डेस्क । जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बुधवार को भोजपुर जिले में हालिया कथित पुलिस मुठभेड़ में जान गंवाने वाले भरत भूषण तिवारी के पैतृक गांव पहुंचे और उसके परिजनों से मुलाकात की। जन सुराज पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि भरत भूषण के परिजनों ने न्याय दिलाने में किशोर से मदद की अपील की थी और उन्हें पंचायत बैठक में आमंत्रित किया था। किशोर ने भोजपुर में संवाददाताओं से कहा, पीड़ित परिवार की मांग बिल्कुल स्पष्ट है।

एनकाउंटर का आदेश देने वाले के खिलाफ हो कार्रवाई

उन्हें न तो पैसा चाहिए, न मुआवजा और न ही सरकारी नौकरी। उन्हें न्याय चाहिए और न्याय तभी मिलेगा जब उस व्यक्ति की हत्या करने वालों तथा ऐसा करने का आदेश देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने मांग की कि न्यायिक जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बजाय कार्यरत न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए और जांच तीन महीने के भीतर पूरी की जाए। किशोर ने कहा कि न्यायिक जांच का दायरा केवल जिला पुलिस प्रशासन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि बिहार के गृह विभाग, विशेष कार्य बल (एसटीएफ), पुलिस महानिदेशक और राज्य के गृह मंत्री की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए।

बिहार पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप

भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में बिलौटी गांव के भरत भूषण तिवारी की पिछले सप्ताह पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने इसे कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ बताते हुए पुलिस पर न्यायेतर हत्या का आरोप लगाया है। जन सुराज पार्टी ने रविवार को पटना में मोमबत्ती मार्च निकालकर तिवारी के लिए न्याय की मांग की थी।

प्रशांत किशोर बुधवार को भोजपुर जिले में हालिया कथित पुलिस मुठभेड़ में जान गंवाने वाले भरत भूषण तिवारी के पैतृक गांव पहुंचे और उसके परिजनों से मुलाकात की। जन सुराज पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि भरत भूषण के परिजनों ने न्याय दिलाने में किशोर से मदद की अपील की थी और उन्हें पंचायत बैठक में आमंत्रित किया था। किशोर ने भोजपुर में संवाददाताओं से कहा, पीड़ित परिवार की मांग बिल्कुल स्पष्ट है।

पुलिस को आत्मरक्षा में कार्रवाई करने का अधिकार

इस बीच, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने पटना में संवाददाताओं से कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना सभी को दुखी करने वाली है। सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।

विपक्ष को इसका राजनीतिकरण करने के बजाय सरकार और न्यायिक समिति के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिल सके।

बिहार में कथित रूप से बढ़ रही मुठभेड़ों के संबंध में पूछे गए सवाल पर कुमार ने कहा कि पुलिस को आत्मरक्षा में कार्रवाई करने का अधिकार है।

30 हजार करोड़ की परियोजनाओं पर मोदी की सख्त समीक्षा, साइबर अपराध पर भी जताई गहरी चिंता

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) की 52वीं बैठक में करीब 30 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली चार बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी सिर्फ लागत नहीं बढ़ाती, बल्कि लोगों और उद्योगों को समय पर मिलने वाले लाभों से भी वंचित कर देती है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को लंबित मुद्दों को मिशन मोड में हल करने और परियोजनाओं की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए । नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री ने सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल से

जुड़ी चार प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया। ये परियोजनाएं चार राज्यों में फैली हुई है और क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक विकास तथा जनकल्याण की दृष्टि से अहम मानी जा रही है। बैठक में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, परियोजनाओं की समयसीमा और बाधाओं को दूर करने पर विशेष जोर दिया गया।

परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पीएम ने निर्देश दिए

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं से जुड़ी सभी जानकारियां, उपयोगिताएं, स्वीकृतियां और जमीनी स्थिति को पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। इससे रुकावटों की पहले से पहचान की जा सकेगी और वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर बेहतर फैसले लिए जा सकेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की। उन्होंने इस अभियान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि जागरूकता फैलाने, मरीजों की निगरानी और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों की एक विशेष टीम बनाई जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए अलग-अलग एजेंसियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। इसके लिए स्पष्ट जवाबदेही, त्वरित कार्रवाई और कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों तथा डिजिटल मंचों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

ई-जीरो एफआईआर को लेकर राज्यों से अपील की गई?

प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वित्तीय नुकसान रोकने और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए समय पर कार्रवाई बेहद जरूरी है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से रोकथाम, जांच, रिपोर्टिंग और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने की अपील की। साथ ही राज्यों से साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित पंजीकरण और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम करने को कहा।

खामेनेई की अंतिम विदाई में शामिल होंगे पीएम मोदी? राष्ट्रपति पजेश्कियन ने दिया ईरान आने का न्योता

नई दिल्ली । ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक, यह निमंत्रण ऐसे समय आया है जब खामेनेई के निधन के बाद ईरान में बड़े पैमाने पर श्रद्धांजलि कार्यक्रमों की तैयारी चल रही है।

कई धार्मिक और सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन

खामेनेई के सम्मान में 5 से 9 जुलाई के बीच कई धार्मिक और सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें 5, 6 और 7 जुलाई को तेहरान और कोम में विशेष समारोह होंगे, जबकि अंतिम श्रद्धांजलि कार्यक्रम 9 जुलाई को मशहद में आयोजित किया जाएगा।

भारत सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार

हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी को मिले इस निमंत्रण पर भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में यह साफ नहीं है कि प्रधानमंत्री इस समारोह में शामिल होंगे या नहीं।

तीन दशकों तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे खामेनेई

गौरतलब है कि खामेनेई करीब तीन दशकों तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे। उनका निधन 28 फरवरी को हुआ था। उनके निधन के बाद यह पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय समारोह होगा, जिसमें दुनिया के कई देशों के नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने लिखित में मांगी माफी

जबलपुर ।लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में बुधवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अदालत में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत कर अपने कथित बयान पर खेद व्यक्त किया गया। मामले की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने अगली सुनवाई गुरुवार के लिए निर्धारित की है। यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर मानहानि परिवाद से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2018 में झाबुआ में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए शिकायतकर्ता का नाम लिया था, जिससे उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। परिवाद पर सुनवाई करते हुए भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किए थे। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहत की मांग की थी। हाईकोर्ट ने पूर्व में सुनवाई के दौरान अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। मंगलवार को हुई सुनवाई में राहुल गांधी की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट का रिकॉर्ड हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया गया। साथ ही 25 जून को निर्धारित सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिए आवेदन भी दाखिल किया गया था। इस आवेदन पर सुनवाई के लिए एकलपीठ ने बुधवार की तारीख तय की थी। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से प्रस्तुत आवेदन में कहा गया कि उनका बयान शिकायतकर्ता के संदर्भ में नहीं था। साथ ही बयान को लेकर खेद भी व्यक्त किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई गुरुवार के लिए निर्धारित कर दी है। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने पक्ष रखा।

सीएम नायडू ने किया देश की सबसे बड़ी निजी सोने के खदान का उद्घाटन

अमरावती । आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले का जोनागिरि इलाका अब देश के गोल्ड मैप पर अपनी खास पहचान बनाने जा रहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यहां देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। करीब 405 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना को जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दक्कन गोल्ड माइन्स लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। परियोजना के तहत सोने के प्रोसेसिंग प्लांट की पहली यूनिट शुरू की जाएगी, जबकि दूसरी यूनिट की आधारशिला भी रखी जाएगी। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, खदान और प्रोसेसिंग प्लांट का ट्रायल रन पूरा हो चुका है। उद्घाटन के बाद यहां व्यावसायिक स्तर पर सोने का उत्पादन शुरू हो जाएगा। जोनागिरि गोल्ड फील्ड्स प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 1,500 एकड़ जमीन आवंटित की है। पहले चरण में 600 एकड़ क्षेत्र में खनन कार्य

***पहले साल 400 किलो सोने निकलने की उम्मीद**

***144 करोड़ रुपये की आय की संभावना**

शुरू होगा, जबकि बाद में बाकी इलाके में भी परियोजना का विस्तार किया जाएगा। उम्मीद है कि पहले साल इस खदान से करीब 400 किलोग्राम सोना निकलेगा। अगले साल उत्पादन बढ़कर 900 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। भविष्य में प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ने के साथ यह परियोजना हर साल लगभग 2 टन सोना उत्पादन करने में सक्षम होगी।

इस परियोजना से लगभग 700 लोगों को सीधे और परोक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। साथ ही, राज्य सरकार को उत्पादित सोने के मूल्य पर 4 प्रतिशत रॉयल्टी भी मिलेगी। अनुमान है कि 400 किलोग्राम उत्पादन पर सरकार को

परियोजना के तहत सोने के प्रोसेसिंग प्लांट की पहली यूनिट शुरू की जाएगी, जबकि दूसरी यूनिट की आधारशिला भी रखी जाएगी। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, खदान और प्रोसेसिंग प्लांट का ट्रायल रन पूरा हो चुका है। उद्घाटन के बाद यहां व्यावसायिक स्तर पर सोने का उत्पादन शुरू हो जाएगा।

करीब 57 करोड़ रुपये और 900 किलोग्राम उत्पादन पर लगभग 144 करोड़ रुपये की आय हो सकती है।

देश के प्रमुख गोल्ड माइनिंग केंद्रों में शामिल हो जाएगा आंध्र प्रदेश

अब तक भारत में सोने की खदानों की चर्चा मुख्य रूप से कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड्स तक सीमित रही है, लेकिन जोनागिरी परियोजना के शुरू होने के बाद आंध्र प्रदेश भी देश के प्रमुख गोल्ड माइनिंग केंद्रों में शामिल हो सकता है।

धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा - खरगे

नेशनल डेस्क।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को प्रदर्शनकारी छात्रों को कथित तौर पर आतंकवादी कहने को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। खरगे ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि देश में कई पेपर लीक होने से करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और नीट पेपर लीक प्रकरण से कई परिवार तबाह हो गए है। खरगे ने दावा किया कि ऐसी स्थिति में शिक्षा मंत्री छात्रों को दहशतगर्द बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, उन्हें देशद्रोही बताया जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश यह नहीं भूला है कि उन्होंने संसद में किसानों के लिए आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल किया था। खरगे ने कांग्रेस की मुहिम छात्रों की गूंज का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा।

भाजपा ने मोहन यादव को बदनाम करने के लिए साजिश की... सीएम पद से हटाने का ढूंढ रही रास्ता - अखिलेश यादव

नेशनल डेस्क । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर कथित भूमि घोटाले के आरोप को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोहन यादव को बदनाम करने के लिए भाजपा ने साजिश की है। अगर मोहन यादव पर ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। ये कोई नई बात नहीं है। वे पहले रियल स्टेट का काम करते थे। क्या भाजपा ये नहीं जानती? ये आरोप इसलिए लग रहा है कि भाजपा रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। अखिलेश ने कहा कि वे मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं इसलिए आरोप लगवा रहे है... इन्हें मध्य-प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाना है। इन दो को इसलिए हटा रहे है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है...उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इस बार साइकिल इतनी तेज चलेगी कि अपने आप मुख्यमंत्री हट जाएंगे। आप को बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार ने उज्जैन में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने का आरोप है दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद यादव के परिवार ने 168 एकड़ जमीन खरीदी, जिसमें से 111 एकड़ उस क्षेत्र में है जहां आगामी सिंहस्थ कुंभ और 2035 मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य प्रस्तावित है।

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर रोक बरकरार

कोलकाता । तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को मानहानि मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी पूर्व में खारिज की गई याचिका को पुनः बहाल (रिस्टोर) करते हुए भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर लगी रोक को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। मामला भाजपा नेता आकाश विजयवर्गीय द्वारा वर्ष 2021 में भोपाल स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर मानहानि परिवाद से जुड़ा है। परिवाद में आरोप लगाया गया था कि नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सार्वजनिक सभा के दौरान अभिषेक बनर्जी ने उन्हें 'गुंडा' कहा था। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस टिप्पणी से उनकी और उनके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। मामले की सुनवाई के

दौरान विशेष न्यायालय ने 12 नवंबर 2025 को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वारंट और परिवाद की वैधता को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि वे एक निर्वाचित सांसद है और उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से पैरवी को लेकर अदालत की नाराजगी सामने आई थी। बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद पर्याप्त पैरवी नहीं होने पर हाईकोर्ट ने 17 जून को याचिका खारिज कर दी थी और गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक भी समाप्त कर दी थी। इसके बाद अभिषेक बनर्जी की ओर से याचिका को पुनः बहाल करने तथा अंतरिम राहत जारी रखने की मांग करते हुए नया आवेदन प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों और परिस्थितियों का अवलोकन किया। इसके बाद अदालत ने याचिका को रिस्टोर करने की अनुमति देते हुए गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर लगी रोक को भी यथावत बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया।

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को मानहानि मामले में एमपी हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनकी खारिज याचिका को बहाल करते हुए भोपाल एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर लगी रोक बरकरार रखी। मामला भाजपा नेता आकाश विजयवर्गीय की ओर से दायर मानहानि परिवाद से जुड़ा है।

जाना था अमृतसर पहुंच गया पाकिस्तान, एयर इंडिया के विमान ने लैंडिंग के दौरान कर दी बड़ी चूक

अमृतसर । एयर इंडिया की एक फ्लाइट सोमवार रात रास्ता भटककर पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में जा घुसी। इसे पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक अथॉरिटी ने चेतावनी देकर वापस भेजा। विमान ने दिल्ली से उड़ान भरी थी और इसे अमृतसर लैंड होना था। पाकिस्तान के एयर स्पेस से जब फ्लाइट लौटी तब तक अमृतसर एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बढ़ गया था, ऐसे में इसे वापस दिल्ली भेज दिया गया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया है कि तकनीकी खराबी के कारण यह फ्लाइट रास्ता भटक गई थी। मामले की जांच की जा रही है। इससे पहले 12 जून को पाकिस्तान की भी पैसेंजर फ्लाइट फ्लाई जिन्ना-9 पूपी 514 खराब मौसम के कारण भारतीय एयरस्पेस में घुस आई थी। लाहौर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद फ्लाइट रास्ता भटक गई थी। हालांकि, तकनीकी गड़बड़ी का अंदेशा होते ही फ्लाइट को वापस पाकिस्तानी एयरस्पेस में लाया गया।

जयराम रमेश की शशि थरूर को दो टूक - कांग्रेस में अलग राय रखने की आजादी, यही हमारी ताकत

नई दिल्ली । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यह विभिन्न विचारों को व्यक्त करने की अनुमति देती है, जो इसकी ताकत है। जयराम रमेश का यह बयान पार्टी के सहयोगी शशि थरूर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात पर पार्टी से अलग रुख अपनाने के कुछ दिनों बाद आया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है जो विचारों को दबाती हो। उन्होंने कहा कि पार्टी में कई अनुभवी और जानकार नेता है, जिनके पास राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर कहने के लिए बहुत कुछ है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक दल है और विभिन्न दृष्टिकोणों को सामने रखने की अनुमति देती है। रमेश की यह टिप्पणी उस विवाद के कुछ दिनों बाद आई है, जब कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर शशि थरूर की टिप्पणी की आलोचना की थी। खेड़ा ने कहा था कि मोदी के प्रति थरूर की प्रशंसा अब इस हद तक पहुंच गई है कि वह ऐसी बातें भी सुन लेते हैं, जो प्रधानमंत्री ने कही ही नहीं। थरूर ने इसके जवाब में कहा था कि भारतीय नागरिक नाविकों की सुरक्षा से जुड़े एक बयान को राजनीतिक रंग दिया जाना असाधारण है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ बैठक के बाद थरूर की ओर से जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति की दिशा में हो रही प्रगति को प्रोत्साहित करने संबंधी टिप्पणी भी पार्टी के कुछ नेताओं को पसंद नहीं आई थी। विवाद के बीच थरूर ने स्पष्ट किया था कि विदेश मामलों की संसदीय समिति का जम्मू-कश्मीर दौरा घाटी की परिस्थितियों का आकलन करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा था कि समिति का ध्यान भारत-पाकिस्तान, भारत-चीन संबंधों और पासपोर्ट सेवाओं सहित विदेश मामलों से जुड़े मुद्दों तक सीमित है।

विविध विचारों को स्थान देती है पार्टी- जयराम

पार्टी लाइन से अलग राय रखने वाले नेताओं के बारे में पूछे जाने पर जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के भीतर पार्टी मंचों पर खुलकर और स्पष्ट चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी कुछ नेता अलग दृष्टिकोण रखते है, लेकिन वह इसे कांग्रेस की ताकत मानते है।

रमेश ने कहा, हम ऊपर से नीचे तक निर्देशित होने वाली पार्टी नहीं है। हम ऐसी पार्टी नहीं है जो विचारों को दबाती हो।हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि संचार विभाग के प्रभारी महासचिव के रूप में अलग-अलग विचार सामने आने से उनका काम कुछ कठिन हो जाता है। इसके बावजूद वह इसे कांग्रेस की ताकत मानते है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में विभिन्न विचारों वाले लोग है, जो खुलकर अपनी बात रखते है और पार्टी उन्हें समाहित करने में सक्षम है। रमेश ने कहा कि कांग्रेस की आधिकारिक और मूल राजनीतिक स्थिति वही मानी जाती है, जिसे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी या पार्टी की ओर से अधिकृत नेता सार्वजनिक रूप से रखते है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग विचार मीडिया में सुर्खियां बनते है और चर्चा का विषय बनते है, लेकिन इससे कांग्रेस के व्यापक स्वरूप का पता चलता है। रमेश ने दावा किया कि कांग्रेस पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से विविध विचारों को अपने भीतर स्थान देती रही है।